

प्रेषक,

जे०पी० जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड  
देहरादून।

2. आयुक्त,  
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल

3. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून:

दिनांक 21 जून, 2016

विषय:- जनहित रिट याचिका सं०-233/2008 श्रीमती बीना बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक-04.07.2013 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त जनहित रिट याचिका सं०-233/2008 श्रीमती बीना बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक-04.07.2013 के अनुपालन में राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-3591(I)/XVIII(II)/2013 दिनांक 13.11.2013 में यह उल्लेख किया गया था कि अग्रिम आदेशों तक नदी श्रेणी में दर्ज किसी भी भूमि पर निर्माण किये जाने की अनुमति न दी जाय।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क निर्माण हेतु रोली (जलमग्न) श्रेणी की भूमि अपरिहार्य स्थिति में ही आवंटन हेतु प्रस्तावित की जाय तथा ऐसी भूमि पर सड़क निर्माण से पूर्व बाढ़ सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए यथासम्भव पुल निर्माण हेतु ही ऐसी भूमि को प्रयोग में लाया जाय।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 13.11.2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(जे०पी० जोशी)

अपर सचिव।

पू०प० संख्या-1015/XVIII(II)/2016 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जे०पी० जोशी)

अपर सचिव।